



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(जसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा पठाशित

शिमला, मंगलवार, १४ नवम्बर, १९९५/२३ कार्तिक, १९१७

हिमाचल प्रदेश सरकार

स्थानीय स्वशासन विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, १८ सितम्बर, १९९५

संख्या एल०एस०जी०-ए०(३) ७/९४.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, १९९४ (१९९४ का अधिनियम संख्यांक १२) की धारा ३१ के साथ पठित धारा ६ और १० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

१. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश नगर निगम (वार्डों का परिसीमन और आरक्षण) नियम, १९९५ है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1994 अभिप्रेत है;

(ख) “पार्षद” से इस अधिनियम के अधीन निर्वाचित पार्षद अभिप्रेत है;

(ग) “उपायुक्त” से सम्बन्धित जिला का उपायुक्त अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए उपायुक्त के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त, अन्य अधिकारी भी है; और

(घ) “प्ररूप” से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके हैं।

3. वार्डों की सीमाएं.—(1) प्रत्येक वार्ड की यथा साध्य समान संख्या होगी और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र, भौगोलिक रूप से संहत और समीपस्थ होगा और प्राकृतिक सीमाएं जैसे सड़कें, पथ, लेन्ज, गलियां, नदियां, नहर, नालियां, जंगल, कटक (रिज), रेलवे लाईन या अन्य ऐसे चिह्न जिन्हें आसानी से भिन्न किया जा सके, होंगे।

(2) प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा।

(3) प्रत्येक वार्ड की सीमाएं चारों दिशाओं में निम्नलिखित रूप में सीमांकित होंगी:—

(1) उत्तर में..... द्वारा सीमाबद्ध

(2) दक्षिण में..... द्वारा सीमाबद्ध

(3) पूर्व में..... द्वारा सीमाबद्ध

(4) पश्चिम में..... द्वारा सीमाबद्ध

4. वार्डों का नाम और संख्या.—प्रत्येक वार्ड इसे क्रमानुसार दी गई संख्या से जाना जाएगा, संख्या के अतिरिक्त वार्ड को एक लोकप्रिय नाम भी दिया जाएगा।

5. वार्डों का परिसीमन.—उपायुक्त, अधिनियम की धारा 6 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र को वार्डों में विभाजित करके, वार्डों के परिसीमन के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करेगा और प्रत्येक वार्ड की सीमाओं को भी परिनिश्चित करेगा और इसे अपने कार्यालय और नगर निगम कार्यालय में निरीक्षण के लिए रखेगा और ऐसे प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्ररूप-II में सूचना जारी करेगा और ऐसी सूचना को अपने कार्यालय और नगर निगम के कार्यालय में चिपका कर नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताओं से आक्षेप/सुझाव आमंत्रित करेगा।

(2) उपायुक्त, सूचना जारी करते समय, नगरपालिका क्षेत्र के मतदाताओं से 10 दिन की अवधि के भीतर प्ररूप-II में वार्ड की किसी भी मतदाता से ऐसे प्ररूप परिसीमन प्रस्ताव के विषय में आक्षेप मंगवाएगा।

6. आक्षेपों का निपटारा.—उपायुक्त, नियम 5 के अधीन आक्षेपों, यदि कोई हों, की प्राप्ति पर, उनकी जाँच करेगा और आक्षेपकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, 10 दिन की अवधि के भीतर उन्हें विनिश्चित करेगा।

7. अपील.—उपायुक्त के आदेश से व्यक्ति नगरपालिका क्षेत्र का कोई मतदाता, ऐसे आदेश के विरुद्ध मण्डलायुक्त के पास 10 दिन की अवधि के भीतर अपील दायर कर सकेगा, जो अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद 10 दिन की अवधि के भीतर इसे विनिश्चित करेगा, और अपने आदेश की सूचना उपायुक्त को देगा इस निमित्त मण्डलायुक्त द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।

8. स्थानों का आरक्षण.—प्रत्येक नगर निगम में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (38) में यथा परिभाषित जनसंख्या के आधार पर सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या, अवधारित की जाएगी और आरक्षण करने के प्रयोजनार्थ कुल जनसंख्या के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता तैयार की जाएगी।

(2) प्रत्येक नगर निगम में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए, नगरपालिका क्षेत्र में उनकी जनसंख्या के अनुपात में वार्ड/वार्डों को आरक्षित किया जाएगा। वार्ड जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक हो, अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए और वार्ड जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों की जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक हो, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(3) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्डों की संख्या एक से अधिक हो, तो वह अगला वार्ड जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की प्रतिशतता सबसे अधिक हो यथा स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए इसी प्रकार आरक्षित किया जाएगा :

परन्तु यदि नगर निगम क्षेत्र में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या के 5 प्रतिशत से कम हो, तो उनके लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं होगा।

(4) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित वार्डों में से वार्डों का एक तिहाई यथा स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए यथा स्थिति वार्डों का आरक्षण भाग्य पत्रक निकाल कर किया जाएगा :

परन्तु यदि उनके लिए आरक्षित वार्डों की संख्या एक से अधिक नहीं है, तो यथा स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं और पुरुषों के लिए आरक्षण विकल्पता प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् होगा :

परन्तु यह और कि यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए, यथा स्थिति, आरक्षित स्थान दो हों तो, कम से कम एक वार्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होगा।

(5) कुल वार्डों में से, उप-नियम (4) के अधीन किए गए आरक्षण सहित, एक-तिहाई वार्डों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और इन स्थानों की संगणना करते समय, विभाजन करने के पश्चात् यदि अतिशेष आधे से कम रह जाता है, तो उसे अवगणित किया जाएगा और यह यदि आधे से अधिक है तो इसे एक मान लिया जाएगा।

(6) जनसंख्या की प्रतिशतता के आधार पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाओं के लिए निर्वाचन का आरक्षण पहले निर्वाचन की तारीख से प्रत्येक पाँच वर्ष के पश्चात् परिवर्तित कर

दिया जाएगा। अगले निर्वाचन के समय आगामी अधिकतम प्रतिशतता की जनसंख्या वाले वार्ड/वार्डों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों जिसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाएं भी सम्मिलित हैं, के लिए आरक्षित होगी और पहले वाला आरक्षित वार्ड, सामान्य श्रेणी के सदस्यों के लिए अनारक्षित रखा जाएगा और पश्चातवर्ती निर्वाचन के लिए यही क्रम चलता रहेगा।

(7) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए जिनमें यथा स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित महिलाएं भी सम्मिलित हैं के लिए आरक्षित वार्डों को अपवर्जित करने के पश्चात् महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण भाग्य पत्रक निकाल कर किया जाएगा।

(8) उपायुक्त, भाग्य पत्रक निकालने के समय और स्थान, तारीख को विनिर्दिष्ट करते हुए, तीन दिन का सुस्पष्ट नोटिस जारी करेगा और ऐसा नोटिस वह अपने कार्यालय नगर निगम के सूचना पट पर चिपकावाएगा और वह इसको नगरपालिका क्षेत्र में डोंडी फिटवाकर भी उद्घोषित करवाएगा। भाग्य पत्रक उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय, स्थान और तारीख को नगरपालिका क्षेत्र के कम से कम तीन विशिष्ट व्यक्तियों और सरकार के तीन राजपत्रित अधिकारियों की उपस्थिति में निकाला जाएगा।

(9) इन नियमों के अधीन महिलाओं के लिए प्रथम निर्वाचन में आरक्षित वार्ड/वार्डों को अगले निर्वाचन के समय भाग्य पत्रक निकालते समय अपवर्जित किया जाएगा और यह क्रम चलता रहेगा :

परन्तु महिलाओं के लिए लगातार दो निर्वाचनों के लिए कोई वार्ड आरक्षित नहीं किया जाएगा।

(10) इस नियम के अधीन निकाले गए भाग्य पत्रक का परिणाम और किए गए आरक्षण को उपायुक्त, द्वारा अन्तिम रूप दिया जाएगा और वह ऐसे आरक्षण के आदेश की प्रति को अपने कार्यालय के और नगर निगम के कार्यालय के सूचना पटल पर चिपका कर व्यापक रूप से प्रचारित करेगा और इस आदेश की एक प्रति सरकार को, राजपत्र में प्रकाशन के लिए भी भेजेगा और यह अधिसूचना, वार्डों के आरक्षण का विनिश्चयात्मक प्रमाण होगी।

स्पष्टीकरण.—इन नियमों के प्रयोजन के लिए हिजड़ा (नपुंसक) महिला के रूप में समझा जाएगा।

9. अन्तिम प्रकाशन.—(1) उपायुक्त, सभी आक्षेपों की सुनवाई करके अन्तिम रूप में विनिश्चय करने के पश्चात् या यदि कोई आक्षेप प्राप्त न हुआ हो, तो इस प्रकार किए गए परिसीमन को, परिसीमन प्रस्ताव प्रारम्भिक प्रकाशन से 45 दिन की अवधि के भीतर, उसी एक प्रति निदेशक, नगर निगम और उपायुक्त के कार्यालयों में और अन्य ऐसे सहज-दृश्य स्थानों पर, जैसा कि उपायुक्त विनिश्चित करे, चिपकाएगा और उपायुक्त इसकी एक प्रति सरकार को भी भेजेगा।

(2) सरकार, नगर निगम के प्रत्येक निर्वाचन से पूर्व वार्डों के परिसीमन और आरक्षण को और उनके चक्रानुक्रम को राजपत्र में अधिसूचित करेगी।

(3) वार्डों के अन्तिम रूप से किए गए परिसीमन और आरक्षण की प्रतियां उपायुक्त और नगर निगम के कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। नगरपालिका क्षेत्र का कोई भी मतदाता परिसीमन और आरक्षण आदेश की प्रति उपायुक्त को 25/- रुपये का संदय करने पर प्राप्त कर सकेगा, और वह उसे तुरन्त दी जाएगी।

10. राज्य निर्वाचन आयोग को सूचना देना.—सरकार, अन्तिम रूप से किए गए परिसीमन और आरक्षण आदेश की प्रति तुरन्त राज्य निर्वाचन आयोग को भिजवाएगी।

11. निरसन और व्यावृत्ति.—अधिसूचना संख्या 4-1/83-ई0 एल0 एन0, तारीख 24-8-1995 द्वारा

1 जारी हिमाचल प्रदेश नगर निगम (निर्वाचन) नियम, 1985 के नियम 3 से 6 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है :

परन्तु ऐसे निरमित नियमों के अधीन लिए गए किसी आदेश या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन विधिमान्य रूप से की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित/-
वित्तायुक्त एवं सचिव।

— — — — —
प्ररूप-I

[नियम 5 (1) देखें]

नगर निगम को वार्डों में बांटने और प्रत्येक वार्ड की सीमाएं परिभाषित करने के प्रस्तावों के प्रकाशन की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि नगर निगम को वार्डों में बांटने और प्रत्येक ऐसे वार्ड की सीमाएं परिभाषित करने का प्रस्ताव, अधोहस्ताक्षरी और नगर निगम के कार्यालयों में आगामी दस दिन के लिए निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।

यदि उक्त प्रस्ताव में अन्तर्विष्ट किसी बात के लिए, कोई व्यक्ति कोई आक्षेप करना चाहे या सुझाव देना चाहे, तो वह इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 10 दिन के भीतर अधोहस्ताक्षरी को प्ररूप-II में भेजा जा सकेगा।

स्थान.....

उपायुक्त।

तारीख.....

— — — — —
प्ररूप-II

[नियम 5 (2) देखें]

सेवा में

उपायुक्त,

.....
.....

विषय.—परिसीमन के प्ररूप प्रस्ताव के लिए आक्षेप।

श्रीमान जी,

..... नगर निगम के विषय में..... को प्रकाशित परिसीमन प्ररूप प्रस्तावों के संदर्भ में।

2. यह कि मैं..... वार्ड नं० क्रम से नगर निगम का मतदाता हूं।

3. यह कि मुझे इस प्रस्तावित प्रल्प के विषय में निम्नलिखित आक्षेप करने/सुझाव देने हैं:—

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

आवेदक,

स्थान

हस्ताक्षर

तारीख

पूरे नाम सहित पता ।

[Authoritative English text of Government notification No. LSG-A (3) 7/94, dated 18-9-1995 as required under clause (3) of Article 343 of the Constitution of India].

LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 18th September, 1995

No. LSG-A (3) 7/94.—In exercise of the powers vested in him under section 31 read with sections 6 and 10 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994, (Act No. 12 of 1994), the Governor, Himachal Pradesh in consultation with the State Election Commission, is pleased to make the following Rules, for the purposes of the said Act, namely :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Municipal Corporation (De-limitation and Reservation of Wards) Rules, 1995.

(2) They shall come into force at once.

2. *Definitions.*—(1) In these rules unless the context otherwise requires:—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Municipal Corporation Act, 1994;

b) “Councillor” means a Councillor elected under Act ;

(c) “Deputy Commissioner” means the Deputy Commissioner of the District concerned and includes such other Officer as may be appointed by the State Government to perform the function of the Deputy Commissioner for the purposes of these rules ; and

(d) “Form” means the Form appended to these rules.

(2) Words and expressions used in these rules but not defined shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. *Limits of Wards.*—(1) As far as practicable each ward shall have equal population and each ward shall be geographically compact and contiguous in area with natural

boundaries, such as roads, paths, lanes, streets, streams, canals, drains, jungles, ridges, Railway lines or such other marks or boundaries which can easily be distinguished.

(2) One Councillor shall be elected from each ward.

(3) The limits of each ward shall be defined in all four directions as follows :—

(1) Bounded on the North by.....

(2) Bounded on the South by.. ..

(3) Bounded on the East by.....

(4) Bounded on the West by.

4. *Name and number of the Wards.*—Each ward shall be known by the number given serially. In addition to the number, a popular name shall also given to the Ward.

5. *De-limitation of Wards.*—(1) The Deputy Commissioner shall make a draft proposal for delimitation of wards by dividing a Municipal area into wards as per provisions contained in section 6 of the Act and shall also define the limits of each ward and shall keep the same open for inspection in his office and in the office of the Municipal Corporation and shall issue a notice in Form-I for inviting objection from the voters of the Municipal area in relation to such proposal by affixing a copy of such notice in his office and in the office of the Municipal Corporation.

(2) While issuing notice, the Deputy Commissioner shall call for objections to such draft delimitation proposal from the voters of the Municipal area within a period of 10 days to be made to him in writing by any voter of the ward in Form-II.

6. *Disposal of Objections.*—The Deputy Commissioner shall, on receipt of the objections, if any, under rule 5 shall inquire into the same and shall decide them within a period of ten days, after giving an opportunity of being heard to an objector.

7. *Appeal.*—Any voter of the Municipal area aggrieved by the order of the Deputy Commissioner may file an appeal to the Divisional Commissioner within a period of 10 days, who after giving an opportunity of being heard to the appellant, shall decide the appeal within a period of ten days and communicate the order to the Deputy Commissioner. The order passed by the Divisional Commissioner in this behalf shall be final.

8. *Reservation of seats.*—(1) In every Municipal Corporation, the population of General Category, Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be determined on the basis of population as defined in clause (38) of section 2 of the Act and the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in relation to the total population shall be worked out for the purpose of making reservation.

(2) In every Municipal Corporation, ward/wards shall be reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population in that Municipal area. The ward having the highest percentage of population of Scheduled Castes shall be reserved for the members of Scheduled Castes and the ward having the highest percentage of population of Scheduled Tribes shall be reserved for the members of the Scheduled Tribes.

(3) If the numbers of wards to be reserved for members of Scheduled Castes or Scheduled Tribes is more than one, then the ward having the next highest percentage

of population of Scheduled Castes/Scheduled Tribes shall be reserved for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, and so on :

Provided that if the total population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in a Municipal Corporation area is less than 5% of the total population then no ward shall be reserved for them.

(4) Out of the wards reserved for members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, one-third of the wards shall be reserved for women members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be. The reservation of wards for Scheduled Castes and Scheduled Tribes women, as the case may be, shall be made by draw of lots :

Provided that if the number of wards reserved is not more than one, then there will be reservation for men and women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, alternatively after every five years :

Provided further that if the number of wards reserved for the members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, is two, then atleast one ward shall be reserved for the women members belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.

(5) Out of the total wards, one-third of the wards shall be reserved for women including the reservation made under sub-rule (4) and in computing these seats if the remainder after dividing is less than half then it will be ignored and if is more than half, it will be taken as one.

(6) The wards reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes on the basis of percentage of population shall be charged after every five years from the date of first election. At the time of next election, the ward/wards, containing the next highest percentage of population shall be reserved for member of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, including women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the ward earlier reserved shall be kept open to the member of the general category and so on for subsequent elections.

(7) The reservation of wards for women, shall be made by draw of lots after excluding the wards which have been reserved for Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates including women belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be.

(8) The Deputy Commissioner shall issue a three days' clear notice specifying therein the date, place and time of the draw of lots and such notice shall be affixed on the notice board of his office and that of the Municipal Corporation and he shall also proclaim it by beat of drums within the Municipal area. The draw shall take place on the date, place and time specified above in the presence of at least three prominent persons of the Municipal Corporation area and three Gazetted Officers of the Government.

(9) The ward/wards reserved for women in the first election under these rules shall be excluded from the draw of lots at the time of next elections and so on :

Provided that no ward shall be reserved for women in two consecutive elections.

(10) The reservation made and results of draw of lots under this rule shall be announced by the Deputy Commissioner and shall be given wide publicity by him by affixing a

Copy of order of such reservation on the notice board of his office and that of the Municipal Corporation and shall also send a copy of the same to the Government for publication of the order in the Official Gazette and this notification shall be the conclusive proof of reservation of wards.

Explanation.—For the purposes of these rules an eunuch shall be treated as a women.

9. Final publication.—(1) After all the objections have been heard and finally decided or no objection has been received, the delimitation so made shall be finalised by the Deputy Commissioner within a period of 45 days from the initial publication of the draft delimitation proposal by affixing a copy of the same in the office of the Deputy Commissioner, Municipal Corporation the Director and at such other conspicuous places as the Deputy Commissioner may decide and he shall also send a copy of the same to the Government.

(2) The Government shall notify the delimitation of wards and reservation of wards and their rotation before every election of the Municipal Corporation in the Official Gazette.

(3) The copies of these finalised delimitation and reserved wards shall be available for inspection in the office of the Deputy Commissioner and the Municipal Corporation. Any voter of the Municipal area can have the copy of the delimitation and reservation order by making payments of Rs. 25/- to the Deputy Commissioner and the same shall be supplied to him immediately.

10. Report to the State Election Commission.—The Government shall cause to be delivered a copy of the final delimitation and reservation order made by it immediately to the State Election Commission.

11. Repeal and Savings.—(1) The rules 3 to 6 of the Himachal Pradesh Municipal Corporation (Election) Rules, 1985, issued vide notification No. 4-1 '83-ELM, dated 24-8-1985 are hereby repealed:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been validly made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order,

Sd/-

Financial Commissioner-cum-Secretary.

FORM-I

[See rule 5(1)]

NOTICE OF PUBLICATION OF THE PROPOSAL FOR DIVIDING THE MUNICIPAL CORPORATION INTO WARDS AND DEFINING THE LIMITS OF EACH WARDS

Notice is hereby given that the proposals for dividing... Municipal Corporation into wards and defining the limits of each such ward shall be available for inspection in the office of the undersigned and the Municipal Corporation during the office hours for the next 10 days.

If any person has any objection or suggestion to anything contained in said proposal the same shall be submitted in Form-II to the undersigned within 10 days from the date of publication of this notice.

Place.....

Deputy Commissioner.

Date.....

FORM-II

[See rule 5 (2)]

To

The Deputy Commissioner,

.....

Subject.—Objection to the draft delimitation proposals.

Sir,

Please refer to the draft delimitation proposals published on.....in respect of.....Municipal Corporation.

2. That I am a voter in ward No.....at Sl. No.....of.....
Municipal Corporation.

3. That I have the following objections/suggestions to these draft proposals :—

(1)

(2)

(3)

(4)

Yours Faithfully,

Place.....

Date.....

Signature
Full Name and Address.